

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक
(लोकेश कुमार गौतम, आर०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या:-
प्रविष्टि दिनांक:-

02 / 2016
07-01-2016

नानूलाल पुत्र हरदेवा जाति खटीक निवासी ग्राम खरेडा तह० टोडारायसिंह जिला टोंक राज०
..... आवेदक

बनाम

1. सोहनलाल पुत्र छोटू जाति खटीक निवासी ग्राम खरेडा तह० टोडारायसिंह जिला टोंक राज.
2. भू आवंटन सलाहकार समिति जरिये उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह ।
3. तहसीलदार टोडारायसिंह

.....प्रतिपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) भू आवण्टन अधिनियम 1970

- उपरिस्थित : (1) श्री सेतराम चौधरी, अभिभाषक आवेदक
(2) श्री महावीर तोगडा, अभिभाषक अप्रार्थी सं० 1

निर्णय

दिनांक 09-03-2018

1- सक्षेप में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का सार इस प्रकार है कि भू-आवण्टन सलाहकार समिति जरिये उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह ने केम्प खरेडा तहसील टोडारायसिंह में दिनांक 03-12-2010 को अप्रार्थी संख्या 1 सोहनलाल पुत्र छोटू जाति खटीक निवासी ग्राम खरेडा तह० टोडारायसिंह को आराजी खसरा नम्बर 68 रकबा 1.23 हे० वाके ग्राम खरेडा में से 0.23 हेक्टेयर तथा खसरा नम्बर 93 रकबा 0.12 हे० कुला रकबा 0.35 हे० भूमि का आवण्टन किये जाने का आदेश पारित किया है, जिसे आवेदक ने आवंटन को विधि विरुद्ध मानते हुए इस आवंटन को निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

2- प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तल की गई एवं आवण्टन पत्रावली मंगवाई गई।

3- आवेदक द्वारा दस्तावेजात में फोटो प्रति नामांतरण सं० 1026, नकल जमाबंदी संवत 2068-71, नक्शा शीट, खसरा परिवर्तनशील संवत 2062, 2070, 2063, 2064, आवंटन आदेश, मिलान क्षेत्रफल, मिसल आवण्टन 11.01.2011, जमाबन्दी संवत 2066-2069, खसरा गिरदावरी संवत 2054-2065, जमाबंदी संवत 2070-2073 वाके ग्राम भासू की फोटो प्रति प्रस्तुत की है। बहस अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

4- विद्वान अभिभाषक आवेदकगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त आवंटन के समय राज्य सरकार द्वारा आवंटन के लिए कोई उद्घोषणा जारी नहीं की गई ना ही शासकीय राजपत्र में इस तरह की उद्घोषणा अधिसूचित की गई, बिना इसके भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता। आवंटन के खसरा नंबर 68 रकबा 1.23 हे. तथा खसरा नंबर 93 रकबा 0.12 हे० पर लगभग 40 वर्षों से आवेदक का ही कब्जा काशत है। प्रतिपक्षी सं० 1 को भूमि आवंटन करने से पूर्व प्रतिपक्षी सं० 2 व 3 द्वारा मौके की वस्तु स्थिति की जांच नहीं करवाई, आवंटित भूमि पर अलाटी का कभी कब्जा नहीं रहा तथा ना ही वर्तमान में उसका कब्जा है, बल्कि उक्त खसरा नंबर में पर आज भी आवेदक का ही कब्जा काशत है, आवेदक को खसरा

जिला कलेक्टर
टोंक

नं० 68 के साबिक खसरा नं० 131 में 1 बीघा जमीन दिनांक 30.06.1986 को ही आवंटित हो चुकी थी परन्तु उक्त आवंटन का राजस्व कर्मचारियों द्वारा अमल नहीं किया गया जिसके लिए आवेदक ने उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह के समक्ष वाद दायर कर रखा है जिससे यह तो स्पष्ट है कि उक्त खसरा नंबरान पर आवेदक का वर्षों से कब्जा काशत है। प्रतिपक्षी सं० 1 ने आवंटन के लिए आवश्यक शर्तों का पालन नहीं किया क्योंकि आवंटन होने के प्रथम वर्ष में आधी व द्वितीय वर्ष में पूरी जमीन पर काशत करना अनिवार्य है। प्रतिपक्षी सं० 1 ने विपक्षी सं० 2 व 3 से सांठ गांठ करके भ्रष्टाचार तरीका अपनाते हुए उक्त खसरा नम्बर का आवंटन अपने हक में कपटपूर्वक व मिथ्या वर्णन के आधार पर बिना किसी कब्जे के करवा लिया, विपक्षी सं० 1 को हुए आवंटन की पालना में राजस्व अभिलेख में वर्तमान में उसके नाम गैर खातेदारी दर्ज है तथा उसे खातेदारी अधिकार नहीं मिले है, विपक्षी सं० 1 आवंटन के लिए पात्र व्यक्ति नहीं था वह भूमिहीन काशतकार की श्रेणी में नहीं आता है, उसके पास लगभग 15-20 बीघा जमीन है लेकिन फिर भी उसने सांठ-गांठ करके कपट पूर्वक व मिथ्यावर्णन के आधार पर उक्त आवंटन करा लिया। इन सभी तथ्यों से आवंटन नियमों के विपरीत होने से अप्रार्थी सं० 1 के हक में किया गया आवंटन को निरस्त फरमाया जावे। अपने कथन की पुष्टि में रूलिंग्स आरआरडी 1984 पेज नं० 378, आरआरडी 1979 पेज 125, आरआरडी 1983 पेज 53 एवं आरआरडी 1982 पेज 576 उद्धरित की है।

5- विद्वान अभिभाषक प्रतिपक्षी सं० 1 की ओर से अपने जवाब प्रार्थना में अंकित तथ्यों का दोराने बहस कथन किया कि भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा विधिवत रूप से उक्त भूमि का आवण्टन प्रतिपक्षी सं० 1 के हक में किया गया है। आवंटित भूमि पर आवंटन से काफी समय पूर्व से ही प्रतिपक्षी सं० 1 का कब्जा काशत चला आ रहा था, इस संबंध में धारा 91 रा.ले.रे.एक्ट के तहत पत्रावली सं० 1906/2001 व 2734/2002 सहित हर वर्ष आवंटित भूमि पर आवंटि के कब्जे के संबंध तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा कार्यवाही की जाती रही थी। उक्त आवंटित भूमि के अडवा भी आराजी ख० नं० 92 व 101 स्वयं आवंटि के कब्जे काशत व खातेदारी की भूमि है और आवंटित भूमि उसकी खातेदारी की भूमि के अडवा होकर स्ट्रीप आफ लेण्ड की तारीफ में आने वाली भूमि होने के कारण एवं आवंटित भूमि पर प्रार्थी/आवंटि का कब्जा होकर उसके खेत में मिली हुई होने के कारण सही रूप से विपक्षी सं० 1 को आवंटित हुई है और आवंटन के पूर्व से लेकर आवंटन के पश्चात और वर्तमान में भी आवंटित भूमि पर आवंटि का कब्जा चला आ रहा है जिसकी पुष्टि खसरा गिरदावरी से भी होती है। आराजी खसरा नंबर 68 का कुल रकबा 1.23 हेक्टेयर है जो कि 5 बीघा से अधिक बनता है और उसमें से मात्र 0.23 हे. भूमि की प्रार्थी/आवंटि को आवंटित हुई है। ऐसी स्थिति में यदि वर्ष 1986 को इस में से केवल 1 बीघा भूमि किसी को आवंटित भी हो गई तो भी उस आवंटन के बाद लगभग 4 बीघा भूमि आवंटन की दिनांक को आवंटन हेतु शेष थी जिसमें से केवल 0.23 हे. भूमि आवंटि को आवंटित हुई है। आवंटित भूमि पर आवंटि को खातेदारी काफी समय पहले ही मिल चुकी है। आवंटि आवंटन की दिनांक को भूमिहीन काशतकार था जबकि आवेदक न तो भूमिहीन था और ना ही आवंटन प्राप्त करने का पात्र था और ना ही आवंटित भूमि पर उसका कभी कब्जा रहा है। आवेदन गलत व निराधार तथ्यों पर पेश किया गया है जो खारिज फरमाया जावे।

6- हमने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, मूल आवंटन पत्रावली एवं बहस उभयपक्ष का ध्यानपूर्वक अवलोकन, मनन एवं परिशीलन किया। भू-आवण्टन सलाहकार समिति जरिये उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह ने केम्प खरेडा तहसील टोडारायसिंह में दिनांक 03-12-2010 को अप्रार्थी संख्या 1 सोहनलाल पुत्र छोटू जाति खटीक निवासी ग्राम खरेडा तह० टोडारायसिंह को आराजी खसरा नम्बर 68 रकबा 1.23 हे० वाके ग्राम खरेडा में से 0.23 हेक्टेयर तथा खसरा

व बिना हलेश
टोंड



नम्बर 93 रकबा 0.12 हे० कुल रकबा 0.35 हे० भूमि का आवण्टन किये जाने का आदेश पारित किया है। आवंटन की दिनांक को भूमिहीन काश्तकार की सीमा से अधिक भूमि आवंटी के नाम हो इसका कोई सबूत आवेदक द्वारा पेश नहीं किया गया है। साबिक 131 मी. के हाल खसरा नंबर 68 का कुल रकबा 1.23 हेक्टेयर में से मात्र 0.23 हे. भूमि की प्रार्थी/आवंटी को आवंटित हुई है। आवंटित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2072-75 में खातेदार प्रतिपक्षी सं० 1 के नाम दर्ज है। ऐसी स्थिति में यदि वर्ष 1986 को इस में से केवल 1 बीघा भूमि किसी को आवंटित भी हो गई तो भी उस आवंटन के बाद लगभग 4 बीघा भूमि आवंटन की दिनांक को आवंटन हेतु शेष थी जिसमें से केवल 0.23 हे. भूमि आवंटी को आवंटित हुई है। आवंटन से पूर्व आवंटन के समय भूमि खाली व सिवायचक थी जो आवंटन योग्य थी। भूमि आवण्टन नियम 14(4) के तहत आवंटी को आवण्टन के प्रथम वर्ष में भूमि के कम से कम 50 प्रतिशत भाग को जोतना पड़ेगा शेष क्षेत्र को दूसरे वर्ष में शेष भाग को काश्त करने के नियम को वर्ष 1999 में संशोधित कर समाप्त कर दिया गया है। आवण्टन पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रतिपक्षी सं०1 के द्वारा विधिवत रूप से भूमि आवण्टन हेतु प्रार्थना पत्र भरकर पेश किये जाने पर ही पटवारी हल्का, भू०अ० निरीक्षक व तहसीलदार के द्वारा भी प्रतिपक्षी सं०1 की भूमि के बारे में रिपोर्ट की गई है जो बरवक्त आवण्टन भू आवण्टन सलाहकार समिति के समक्ष मौजूद थी। आवण्टन की सिफारिश आवंटन सलाहकार समिति द्वारा की गई है। राजस्व रिकार्ड में भूमि सिवायचक थी ओर अप्रार्थी सं० 1को भी इसी भूमि में से आवण्टन दिनांक 03-12-2010 को ही किया गया था। आवेदक बरवक्त आवण्टन मौके पर मौजूद था ओर यदि उसे प्रश्नगत आवण्टन के बाबत कोई आपत्ति थी तो वह आवण्टन सलाहकार समिति के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र था। जहां तक उद्घोषणा जारी नहीं करने का प्रश्न है तो यहाँ उल्लेख किया जाना उचित होगा कि प्रश्नगत आवण्टन प्रशासन गाँव के संग अभियान 2010 में मजमेआम में पूर्ण कोरम होने पर किया गया है। आवेदक ने अपने कब्जे के बारे में दस्तावेज प्रस्तुत तो किये हैं फिर भी यदि आवेदक का विवादित भूमि पर कब्जा भी है तो वह एक अतिक्रमी की हैसियत ही रखता है तथा अतिक्रमित भूमि आवण्टन योग्य मानी गई है। यहां यह उल्लेखनीय है कि आवेदक ने आवंटन दिनांक 14.01.2011 के विरुद्ध प्रार्थना पत्र पेश किया है किन्तु उक्त आवंटन से संबंधित कोई साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। प्रतिपक्षी सं० 1 को जो आवंटन विवादित भूमि का किया गया है वह आवंटन पत्रावली अनुसार दिनांक 03.12.2010 का है। अतः उक्त सभी तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थी सारहीन होने से खारिज किया जाना उचित है।

आदेश

7. फलतः उपरोक्त विवेचनो के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 09.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(लोकेश कुमार गौतम)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक-राज०